भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3271

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

3271. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और अधूरे कार्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीड जिले और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति दयनीय है और यदि हां, तो उनकी मरम्मत और निधि की स्वीकृति के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और नए मार्गों की स्वीकृति के लिए कौन सी विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और महाराष्ट्र के कितने गांव उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं;

(ङ) लंबित फ्लाईओवर, बाईपास और चौड़ीकरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी के कारण कुछ परियोजनाओं में विलंब हुआ है और यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) महाराष्ट्र राज्य में 57,360 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित 2,612 किलोमीटर की लंबाई वाली 116 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदायी रखरखाव एजेंसियों के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से तीन तरीकों से निष्पादित की जाती हैं, अर्थात (i) निर्माण संचालन और हस्तांतरण (बीओटी), (ii) हाइब्रिड एनुइटी मॉडल (एचएएम) और (iii) इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी)। निर्माण संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) पर परियोजनाओं के लिए रखरखाव सहित रियायत अवधि 15 से 20 वर्ष है और हाइब्रिड एनुइटी मॉडल (एचएएम) पर आम तौर पर 15 वर्ष है। रियायतग्राही परियोजना की रियायत अवधि के भीतर संबंधित एनएच खंडों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। केवल ईपीसी

परियोजनाओं के मामले में, बिटुमिनस फुटपाथ कार्यों के लिए दोष देयता अवधि (डीएलपी) 5 वर्ष और कंक्रीट फुटपाथ कार्यों के लिए 10 वर्ष है।

टोल-संचालन-हस्तांतरणण (टीओटी) और इनविट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) परियोजनाओं के लिए, रखरखाव सहित रियायत अवधि 20 से 30 वर्ष है। संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि आम तौर पर 9 वर्ष है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष सभी खंडों के लिए, जहां डीएलपी समाप्त हो गया है या बीओटी/एचएएम / टीओटी / इनविट परियोजना की किसी भी रियायत अवधि के तहत नहीं है, सरकार ने कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। जबकि एसटीएमसी कार्य आम तौर पर 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं।

सरकार ने डीपीएल के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए खंडों के लिए पीबीएमसी योजना के तहत 28.56 करोड़ रुपये की लागत से 38 किलोमीटर की लंबाई वाले कार्य और एसटीएमसी योजना के तहत 0.73 करोड़ रुपये की लागत से 1.041 किलोमीटर की लंबाई वाले एक कार्य को मंजूरी दी है।

(ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत स्वीकृत किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में पीएमजीएसवाई योजना के तहत 3442.23 करोड़ रुपये की लागत वाली 804 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 3540 किलोमीटर लंबी सड़क और 213 पुल शामिल हैं, जिनसे 8187 गांवों को लाभ हुआ है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले किसी भी दुर्घटना की सूचना ई-डीएआर पोर्टल पर दी जाती है और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए तकनीकी सलाहकारों द्वारा दुर्घटना का विस्तृत कारण विश्लेषण किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए तत्काल अल्पकालिक उपाय जैसे सड़क चिह्नों, संकेतक, क्रैश बैरियर, उठी हुई फुटपाथ मार्कर, सीमांकन, मीडियन ओपनिंग को बंद करना, यातायात को कम करने के उपाय आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे के स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास / ओवरपास आदि के निर्माण जैसे दीर्घकालिक सुधार उपायों को भी दुर्घटना स्थलों की सड़क सुरक्षा ऑडिट के आधार पर लागू किया जाता है।

(ड.) मौजूदा मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) विवादों, भूमि अधिग्रहण में देरी, वन और वन्यजीव मंजूरी, जन उपयोगी सुविधाओं के हस्तांतरणण में देरी और अन्य निर्माण-पूर्व गतिविधियों के साथ-साथ कुछ ठेकेदारों के साथ नकदी प्रवाह के मुद्दों और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कुछ एनएच परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई है। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जन उपयोगी सुविधाओं के हस्तांतरणण के सभी लंबित मुद्दों को राज्य सरकार के साथ

घनिष्ठ समन्वय से काफी हद तक हल कर लिया गया है और शेष कार्य नियमित निगरानी के साथ कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए "भूमी राशी" पोर्टल और जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करना, वन और पर्यावरण मंजूरी को तेजी से सुविधाजनक बनाने के लिए "परिवेश" पोर्टल का नवीनीकरण करना, रेलवे से रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी) की सामान्य व्यवस्था ड्राइंग (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति को सक्षम बनाना, और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग में चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/रुकावटों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाना शामिल है। रेलवे ने विभिन्न अनुमोदनों के लिए परिभाषित समय सीमा के साथ रेलवे से संबंधित मंजूरी के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदार की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तरीकों का उपयोग करके एक मजबूत ढांचा (फ्रेमवर्क) स्थापित किया है। परियोजना की प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे कि तीन साल से अधिक समय तक विलंबित या सौंपे जाने/नियुक्ति के लिए लंबित परियोजनाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, कई राज्य सरकारें परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए बढ़ाया जाता है।

*****